MPS 003 EXPECTED QUESTIONS

IMPORTANT FOR DECEMBER 2024

In Hindi & English both

ROLE OF PARLIAMENT IN THE SOCIO ECONOMIC TRANSFORMATION OF INDIA

Role of Parliament in the Socio-Economic Transformation of India

Legislative Reforms

Parliament enacts laws to address socio-economic challenges such as poverty, unemployment, and inequality.

Landmark legislations like the Right to Education Act (2009), MGNREGA (2005), and the GST Act (2017) have significantly impacted India's socio-economic landscape.

संसद सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को हल करने के लिए कानून बनाती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), मनरेगा (2005), और जीएसटी अधिनियम (2017) जैसे ऐतिहासिक कानूनों ने भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर बड़ा प्रभाव डाला है।**

Budgetary Oversight

The Parliament reviews and approves the Union Budget, ensuring that resources are allocated to welfare schemes and developmental projects.

Special attention is given to sectors like healthcare, education, infrastructure, and agriculture.

Scholarly Minds

संसद केंद्रीय बजट की समीक्षा और अनुमोदन करती है, यह सुनिश्चित करती है कि संसाधन कल्याण योजनाओं और विकास परियोजनाओं को आवंटित किए जाएं।

स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कृषि जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

Policy Formulation and Accountability

Parliamentary debates and discussions shape policies aimed at reducing disparities and promoting growth.

Committees like Public Accounts Committee (PAC) ensure government accountability in implementing socio-economic programs.

संसदीय बहसें और चर्चाएँ असमानताओं को कम करने और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आकार देती हैं।

लोक लेखा समिति (पीएसी) जैसी समितियाँ सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

Welfare and Empowerment

Parliament has introduced various welfare schemes for marginalized groups, including the SC/ST Prevention of Atrocities Act and Women Reservation Bill (proposed).

Empowerment initiatives through laws like the PESA Act (1996) aim to strengthen tribal communities.

संसद ने हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और महिला आरक्षण विधेयक (प्रस्तावित)।

पेसा अधिनियम (1996) जैसे कानूनों के माध्यम से सशक्तिकरण पहल जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती हैं।

Representation of Diverse Interests

By representing various sections of society, Parliament ensures inclusive growth.

Scholarly Minds

It provides a platform for voicing the concerns of underrepresented groups, ensuring equitable socio-economic policies.

संसद समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करके समावेशी विकास सुनिश्चित करती है।

यह कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है और समान सामाजिक-आर्थिक नीतियाँ सुनिश्चित करती है।

Addressing Social Issues

Through laws and debates, Parliament tackles issues like gender inequality, child labor, and caste discrimination.

Acts such as the Dowry Prohibition Act (1961) and the Juvenile Justice Act (2015) highlight its role in social reforms.

कानूनों और बहसों के माध्यम से संसद लिंग असमानता, बाल श्रम और जातीय भेदभाव जैसे मुद्दों का समाधान करती है।

दहेज निषेध अधिनियम (1961) और किशोर न्याय अधिनियम (2015) जैसे कानून सामाजिक सुधारों में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं।

Economic Liberalization and Modernization

Parliament played a pivotal role in economic reforms, particularly during the 1991 liberalization phase.

Laws facilitating FDI, privatization, and entrepreneurship have transformed India's economic landscape.

संसद ने 1991 के उदारीकरण चरण के दौरान आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), निजीकरण, और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कानूनों ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है।

Monitoring Implementation of Programs

Parliament ensures proper implementation of flagship schemes like Swachh Bharat Abhiyan, Skill India, and Ayushman Bharat.

Scholarly Minds

It monitors outcomes and suggests improvements through reports and inquiries.

संसद स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

यह परिणामों की निगरानी करती है और रिपोर्टों और पूछताछ के माध्यम से सुधारों का सुझाव देती है।

In essence, the Parliament serves as the cornerstone of India's socio-economic transformation, ensuring progress through legislation, policy-making, and oversight.
सार रूप में, संसद भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का आधार स्तंभ है, जो कानून, नीतिनिर्माण और निगरानी के माध्यम से प्रगति सुनिश्चित करती है।

CAUSES OF OVER URBANISATION IN INDIA. HOW CAN THIS BE REDUCED

Causes of Over-Urbanization in India

Rural-Urban Migration

Lack of employment opportunities, poor infrastructure, and agricultural distress in rural areas push people towards cities for better prospects.

Cities offer perceived advantages like jobs, healthcare, and education, leading to an influx of migrants.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी, बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति और कृषि संकट लोगों को बेहतर संभावनाओं के लिए शहरों की ओर ले जाते हैं।

शहरों में नौकरियां, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी सुविधाओं का आकर्षण अधिक प्रवासियों को खींचता है।

Population Growth

High birth rates in urban areas add to the existing population burden.

Combined with migration, this leads to overcrowding in cities.

Scholarly Minds

शहरी क्षेत्रों में उच्च जन्म दर मौजूदा जनसंख्या बोझ को बढ़ाती है।

प्रवास के साथ मिलकर यह शहरों में भीड़भाड़ को जन्म देता है।

Industrialization

Rapid industrial growth around urban centers creates job opportunities, attracting workers from rural areas.

This unplanned urban growth leads to congestion and inadequate housing.

शहरी केंद्रों के आसपास तेज औद्योगिक विकास रोजगार के अवसर पैदा करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को आकर्षित करता है।

यह अनियोजित शहरी विकास भीड़भाड़ और अपर्याप्त आवास की समस्या को जन्म देता है।

Lack of Balanced Regional Development

Development is concentrated in a few cities, while rural and small-town areas remain neglected.

This disparity drives migration to urban hubs.

विकास कुछ शहरों में केंद्रित है, जबकि ग्रामीण और छोटे शहरों के क्षेत्र उपेक्षित रहते हैं।

यह असमानता शहरी केंद्रों में प्रवासन को बढ़ावा देती है।

Inadequate Urban Planning

Poor planning and governance fail to address the increasing urban population.

Insufficient infrastructure like roads, water supply, and sanitation aggravates urban issues.

खराब योजना और प्रशासन बढ़ती शहरी आबादी को संभालने में विफल रहते हैं।

सड़कों, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं शहरी समस्याओं को और बढ़ा देती हैं।

Better Lifestyle in Cities

Scholarly Minds

The allure of a modern lifestyle, entertainment, and better living standards in cities attracts people.

Rural areas often lack such amenities, causing population shifts.

शहरों में आधुनिक जीवनशैली, मनोरंजन और बेहतर जीवन स्तर का आकर्षण लोगों को खींचता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या का पलायन होता है।

Measures to Reduce Over-Urbanization

Promoting Rural Development

Invest in rural infrastructure like roads, schools, and healthcare facilities to improve living standards.

Provide better agricultural support and non-farm employment opportunities.

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं में निवेश करें ताकि जीवन स्तर में सुधार हो।

कृषि समर्थन और गैर-कृषि रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करें।

Decentralization of Industries

Establish industries and business hubs in small towns and rural areas to create local job opportunities.

Reduce the concentration of economic activities in a few cities.

छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना करें ताकि स्थानीय रोजगार के अवसर बन सकें।

आर्थिक गतिविधियों का कुछ ही शहरों में केंद्रीकरण कम करें।

Affordable Housing and Infrastructure

Develop affordable housing schemes to tackle urban slums.

Scholarly Minds

Improve urban infrastructure like public transport, waste management, and water supply.

शहरी झुग्गियों को खत्म करने के लिए किफायती आवास योजनाओं का विकास करें।

सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन और जल आपूर्ति जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करें।

Strengthening Urban Planning

Implement strict urban planning regulations to prevent unplanned growth.

Focus on satellite towns and smart cities to distribute the population load.

अनियोजित विकास को रोकने के लिए सख्त शहरी नियोजन नियम लागू करें।

उपग्रह शहरों और स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि जनसंख्या का भार विभाजित किया जा सके।

Education and Awareness

Educate people about the challenges of over-urbanization and encourage staying in their regions.

Promote entrepreneurship in rural areas to reduce dependence on urban centers.

अत्यधिक शहरीकरण की चुनौतियों के बारे में लोगों को शिक्षित करें और अपने क्षेत्रों में रहने के लिए प्रेरित करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दें ताकि शहरी केंद्रों पर निर्भरता कम हो।

Population Control Measures

Strengthen family planning programs to manage population growth in urban areas.

Spread awareness about the benefits of small family norms.

शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत करें।

Scholarly Minds

छोटे परिवार के नियमों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाएं।

By addressing the root causes and implementing these measures, over-urbanization in India can be effectively managed.
मूल कारणों को हल करके और इन उपायों को लागू करके, भारत में अत्यधिक शहरीकरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।

Scholarly Minds